एमएसएमई : भारत अर्थव्यवस्था की धड़कन

रोजगार, नवाचार और आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार

नयी दिल्ली, 29 जून भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती का आकलन अक्सर बड़े उद्योगों, विशाल कॉरपोरेट घरानों और ऊंची विकास दर से किया जाता है, लेकिन देश की वास्तविक आर्थिक शक्ति उन करोड़ों सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में निहित है, जो गांवों, कस्बों और छोटे शहरों से लेकर महानगरों तक रोजगार, उत्पादन नवाचार की नई इबारत लिख रहे हैं.

यदि बड़े उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, तो एमएसएमई उसकी धड़कन हैं, जो विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करते हैं. हर वर्ष 27 जून को मनाया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस उन करोड़ों उद्यमियों, कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और नवाचार से जुड़े युवाओं के योगदान को सम्मान देने का अवसर है, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने परिश्रम और संकल्प से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है. यह क्षेत्र केवल आर्थिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तिकरण, क्षेत्रीय संतुलन, स्थानीय संसाधनों के उपयोग और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सबसे प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है. हालांकि, समय पर ऋण न मिलना, बड़े खरीदारों द्वारा भुगतान में देरी, तकनीकी पिछड़ापन, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक बाजार की चुनौतियां आज भी इस क्षेत्र के सामने गंभीर मुद्दे हैं. यदि इन समस्याओं का प्रभावी समाधान करते हुए हरित तकनीक, डिजिटलीकरण, ई-कॉमर्स, और गुणवत्ता मानकों को प्राथमिकता दी जाए, तो एमएसएमई क्षेत्र विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने का सबसे सशक्त माध्यम बन सकता है.

> देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 30 प्रतिशत, विनिर्माण उत्पादन में 45 प्रतिशत से अधिक तथा कुल निर्यात में 40 से 45 प्रतिशत तक योगदान देने वाला एमएसएमई क्षेत्र कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगारदाता है. करोड़ों लोगों की आजीविका इसी क्षेत्र से जुड़ी हुई है. सरकार द्वारा एमएसएमई की नई परिभाषा, उद्यम पंजीकरण, क्रेडिट गारंटी योजनाएं, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम), एक जिला-एक उत्पाद (ओडीओपी), ओएनडीसी और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी पहलों ने छोटे उद्यमों को विस्तार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं.

पीपीएफ में 45 लाख से करोड़पति

नयी दिल्ली, 29 जून पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) आज भी देश की सबसे भरोसेमंद दीर्घकालिक बचत योजनाओं में शामिल है. सुरक्षित निवेश, गारंटीड रिटर्न और टैक्स में छूट की वजह से यह योजना नौकरीपेशा और मध्यम वर्ग के निवेशकों की पहली पसंद बनी हुई है. मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिल रहा है. यदि कोई निवेशक 30 वर्ष की उम्र से हर वित्त वर्ष की शुरुआत में 5 अप्रैल तक 1.5 लाख रुपये जमा करता है और 60 वर्ष की आयु तक लगातार निवेश जारी रखता है, तो वह करीब 1.54 करोड़ रुपये का फंड तैयार कर सकता है. इस अवधि में कुल 45 लाख रुपये का निवेश होगा, जबकि लगभग 1.09 करोड़ रुपये केवल ब्याज के रूप में मिल सकते हैं.

गोयल ने एथेंस में मंत्री से की मुलाकात

नयी दिल्ली, 29 जून यूनान की यात्रा पर गये केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एथेंस में वहां के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस के साथ एक बैठक की.

श्री गोयल ने इस बैठक को 'सार्थक' बताते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, ' हमने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग में विस्तार और आपूर्ति श्रंखलाओं की मजबूती के ज़रिए भारत-यूनान आर्थिक साझेदारी को अधिक सुदृढ़ करने पर चर्चा की. ' दोनों मंत्रियों ने दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए विनिर्माण, स्टार्ट-अप और उभरती हुई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मौकों पर भी बात की.

श्री गोयल पिछले सप्ताह ब्रिटेन की अपनी यात्रा पूरी कर के एक उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ एथेंस पहुंचे हैं. इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, निवेश प्रवाह और रणनीतिक आर्थिक सहयोग का विस्तार करना है.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उनकी यूनान यात्रा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को सुदृढ़ करने, नवाचार-आधारित विकास को प्रोत्साहन देने और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारत की व्यापार और निवेश कूटनीति को आगे बढ़ाने की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है.

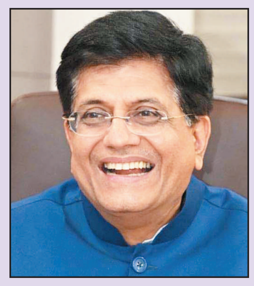

> मंत्री गोयल यूनान के अपने प्रवास में एथेंस चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसीसीआई) के तत्वावधान में आयोजित बैठक में भारत और यूनान के उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे. इन कार्यक्रम में बुनियादी ढांचा, डिजिटलीकरण और रक्षा, तथा खाद्य एवं कृषि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की जाएगी. भारतीय व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल उन्नत विनिर्माण और प्रौद्योगिकी-आधारित क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए यूनान की प्रमुख कंपनियों का दौरा भी करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच औद्योगिक तालमेल बेहतर होगा.

मारुति सुज़ुकी की पांच स्टार्टअप के साथ सहयोग की घोषणा

नयी दिल्ली, 29 जून देश की सबसे बड़ी यात्री वाहन कंपनी मारुति सुज़ुकी इंडिया ने परिचालन दक्षता बढ़ाने और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य क्षेत्रों में समाधान विकसित करने के लिए पांच स्टार्टअप कंपनियों के साथ सहयोग की घोषणा की है.

कंपनी ने सोमवार को बताया कि ये पांच स्टार्टअप कंपनियां मिनीमाइंस, ईजवर्क एआई, सर्वम् एआई, सिफ्टली और कोडमेट एआई हैं. ये सभी मारुति सुज़ुकी इनक्यूबेशन प्रोग्राम के पांचवें बैच के विजेता हैं. इस कार्यक्रम का आयोजन आईआईएम बेंगलुरु के उद्यमिता एवं स्टार्टअप सहायता केंद्र के सहयोग से किया जाता है.

मारुति सुज़ुकी इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिसाशी ताकेउची ने कहा, 'मारुति सुज़ुकी में हम वास्तविक व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए स्टार्टअप के साथ मिलकर नवाचारी और व्यावहारिक समाधान विकसित करने पर लगातार काम कर रहे हैं. हमें पांच और स्टार्टअप के साथ सहयोग करने की खुशी है.

चिकित्सा उपकरण उद्योग के लिए वित्तीय सहायता प्रस्ताव

नयी दिल्ली, 29 जून रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग ने चिकित्सा उपकरण उद्योग को सुदृढ़ बनाने की योजना के तहत पात्र संस्थाओं से आवेदन आमंत्रित किये हैं. इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना, इस क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला को मजबूत बनाना है. रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सीमांत निवेश योजना और चिकित्सा उपकरण नैदानिक अध्ययन सहायता योजना के तहत आवेदन जमा कराये जा सकते हैं.

महाराष्ट्र बांस विकास मंडल समझौता

सास्ती ओपन कास्ट खदान की ओवर बर्डन डंप पर विकसित होगी बांसारोपण परियोजना

नागपुर, 29 जून. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (वेकोलि) ने सतत खनन एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र बांबू विकास मंडल (एमबीडीबी), नागपुर के साथ सस्ती ओपन कास्ट खदान, बल्लारपुर क्षेत्र की ओवरबर्डन (ओबी) डंप भूमि पर वाणिज्यिक बांसारोपण परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है.

यह एमओयू, वेकोलि के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक डॉ. हेमंत शरद पांडे, निदेशक (वित्त) श्री बिक्रम घोष, निदेशक (तकनीकी/योजना एवं परियोजना) श्री संदीप परांजपे की उपस्थिति में वेकोलि के निदेशक (तकनीकी/संचालन) श्री आनंदजी प्रसाद एवं महाराष्ट्र बांबू विकास मंडल के प्रबंध निदेशक श्री कल्याण कुमार ने हस्ताक्षरित किया. इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे.

इस अवसर पर डॉ. हेमंत शरद पांडे ने कहा कि वेकोलि केवल कोयला उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि सतत विकास एवं हरित भविष्य के निर्माण के लिए भी प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक बांसारोपण जैसी पहलें खनन के बाद भूमि के उत्पादक उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों के लिए नए आर्थिक अवसर भी सृजित करेंगी. इस एमओयू के अंतर्गत सस्ती ओपन कास्ट खदान की 19.75 हेक्टेयर पुनर्वासित खनन भूमि पर लगभग 21,942 बांस पौधों का रोपण किया जाएगा. परियोजना के प्रारंभिक पांच वर्षों में वेकोलि द्वारा लगभग 1.33 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. वहीं महाराष्ट्र बांबू विकास मंडल द्वारा बांस की खेती, पौधरोपण विकास, सिंचाई, रखरखाव, कटाई, विपणन तथा उत्पाद की बिक्री की संपूर्ण जिम्मेदारी निभाई जाएगी.

> यह परियोजना 15 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगी. इसके अंतर्गत एक पारदर्शी राजस्व-साझेदारी मॉडल अपनाया गया है, जिसके अनुसार परियोजना से प्राप्त शुद्ध लाभ का 85 प्रतिशत हिस्सा वेकोलि को प्राप्त होगा, जबकि 15 प्रतिशत राशि महाराष्ट्र बांबू विकास मंडल को सुविधा शुल्क के रूप में दी जाएगी. अनुमान है कि परियोजना सातवें वर्ष में वित्तीय संतुलन प्राप्त कर लेगी.

घरेलू निवेश से शेयर बाजार को मजबूती

नयी दिल्ली, 29 जून टैक्स सुधारों, नीतिगत समर्थन और निवेशकों की बदलती बचत प्रवृत्ति के कारण भारतीय शेयर बाजार में घरेलू पूंजी का प्रवाह लगातार मजबूत हो रहा है. बैंक जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार, वर्षों में किए गए कर सुधारों ने इक्विटी निवेश को पहले की तुलना में अधिक आकर्षक बना दिया है. यही वजह है कि पिछले दो वर्षों में बाजार से अपेक्षाकृत सीमित रिटर्न मिलने के बावजूद घरेलू निवेशकों का भरोसा कायम रहा. रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की मौजूदा व्यवस्था, डेट म्यूचुअल फंड पर टैक्स नियमों में बदलाव, इंडेक्सेशन लाभ की समाप्ति जैसे नीतिगत निर्णयों ने निवेशकों के लिए इक्विटी को अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी विकल्प बना दिया है.

सोना-चांदी पर दबाव, सतर्क रहें निवेशक

डॉलर की मजबूती और वैश्विक घटनाक्रम तय करेंगे बाजार की चाल

नयी दिल्ली, 29 जून इस सप्ताह सोना और चांदी के बाजार में उतार-चढ़ाव बने रहने की संभावना है. बाजार अमेरिकी डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक संकेतों और पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण कीमती धातुओं की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है.

ऐसे में निवेशकों को जल्दबाजी में खरीद या बिक्री करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय बाजार के संकेतों और प्रमुख आर्थिक आंकड़ों पर नजर रखनी चाहिए.

पिछले सप्ताह घरेलू वायदा बाजार में सोना और चांदी दोनों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई.

> मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर अगस्त डिलीवरी वाले सोने के वायदा भाव में करीब 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई, जबकि सितंबर डिलीवरी वाली चांदी में छह प्रतिशत से ज्यादा की कमजोरी दर्ज की गई. यह गिरावट निवेशकों की सतर्कता और वैश्विक बाजार में बने दबाव का संकेत है.

गिरावट के साथ बंद हुआ बाजार

सेंसेक्स 372 अंक और निफ्टी 79 अंक फिसला

नयी दिल्ली, 29 जून सप्ताह के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार दबाव में बंद हुआ. वैश्विक बाजारों से मिले कमजोर संकेतों और चुनिंदा क्षेत्रों में बिकवाली के चलते निवेशकों का रुझान सतर्क बना रहा.

कारोबार के अंत में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 372.10 अंक टूटकर 76,728.37 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई का निफ्टी-50 सूचकांक 79 अंक की गिरावट के साथ 23,977 अंक पर आ गया. दिनभर बाजार में उतार-चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन अंतिम घंटों में बिकवाली तेज होने से प्रमुख सूचकांक लाल निशान में बंद हुए. वैश्विक आर्थिक संकेतों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों और आगामी आर्थिक आंकड़ों को लेकर निवेशकों ने सतर्क रुख अपनाया.

आगरा की बेटी, 180 स्टोरों का सफर

फ्रेंचाइजी मॉडल ने छोटे शहरों में दिलाई बड़ी सफलता.

2027 तक 100 करोड़ रुपए राजस्व का लक्ष्य

नयी दिल्ली, 29 जून कॉर्पोरेट नौकरी की सुरक्षित जिंदगी छोड़कर अपना व्यवसाय शुरू करना आसान नहीं होता, लेकिन आगरा की नीलम सिंह ने यह जोखिम उठाकर साबित कर दिया कि मजबूत इरादे, अनुशासन और सही रणनीति से छोटे सपनों को भी बड़े कारोबार में बदला जा सकता है.

महज 250 वर्ग फुट की एक छोटी-सी दुकान और अपनी वर्षों की बचत से शुरू हुआ उनका सफर आज 'द बर्गर कंपनी' के 180 से अधिक आउटलेट्स तक पहुंच चुका है. बिना किसी बाहरी निवेश के खड़ा किया गया यह ब्रांड अब देश के कई राज्यों में अपनी पहचान बना चुका है और करोड़ों रुपये के कारोबार की ओर तेजी से बढ़ रहा है. आगरा के एक साधारण परिवार से आने वाली नीलम सिंह ने प्रबंधन की पढ़ाई पूरी करने के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों में नौकरी की. अच्छी सैलरी मिलने के बावजूद उनका सपना अपना कारोबार शुरू करने का था. इसी उद्देश्य से उन्होंने कई वर्षों तक बेहद सादगी से जीवन बिताया और अपनी आय से पांच लाख रुपये की बचत की. बाद में अपने पति नीतेश धनखड़ के सहयोग और निजी संसाधनों के साथ वर्ष 2018 में गुरुग्राम में 'द बर्गर कंपनी' का पहला आउटलेट शुरू किया.

समाचार विशेष

राजनीति में तोड़फोड़ के बीच आई गुड न्यूज

चेन्नई. महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में पार्टियों की टूटने के बीच दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में बुधवार को दिन भावुक क्षण लेकर आया. पूर्व केंद्रीय मंत्री अंबुमणि महीनों बाद पिता रामदास से मिले, उनके पैर छुए और रोते हुए उन्हें गले लगाकर सुलह की.

पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास अपने परिवार के साथ पिता के घर पर पहुंचे और घुटने के बाद पिता के चरणों में माथा टेका. पिछले काफी वक्त से पिता-पुत्र की राह अलग थी. यह भावुक वाकया टिंडीवनम के पास थैलपुरम फार्महाउस में हुआ. पिता-पुत्र के मिलन ने साबित कर दिया है कि खून सचमुच पानी से गाढ़ा होता है. यह सुलह सीनियर रामदास की शादी की 61वीं सालगिरह के मौके पर उनके फार्महाउस पर हुई ढाई घंटे की दुर्लभ पारिवारिक मुलाकात के दौरान हुई. इस मौके पर माता-पिता का आशीर्वाद लेने के लिए अंबुमणि अपनी पत्नी, तीन बेटियों, दामाद, पोते-पोतियों और सबसे छोटी बहन के साथ फार्महाउस पहुंचे. उनके पहुंचने पर घर के कर्मचारियों ने पारंपरिक आरती की रस्म निभाई और बुरी नजर से बचाने के लिए नारियल फोड़ा.

पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) का सफर- डॉ. एस. रामदास ने 1989 में पट्टाली मक्कल काची पार्टी की स्थापना की थी. पेशेवर डॉक्टर से रामदास ने तमिलनाडु में वन्नियार आंदोलन चलाया और उत्तरी तमिलनाडु की शक्तिशाली पिछड़ी जाति वन्नियार समुदाय के हक की आवाज उठाई थी. रामदास ने केवल गठबंधन की राजनीति की और द्रविड़ पार्टियों के बीच झूलते हुए हमेशा जीतने वाले पक्ष का साथ दिया. 2001 के विधानसभा चुनाव में पीएमके ने 20 सीटें जीतीं. इसके बाद, 2004 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार को समर्थन देकर रामदास ने अपने बेटे अंबुमणि रामदास को देश का सबसे युवा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनवाया.

> **आमसभा में हुई थी तीखी अनबन**
>
> पिता और बेटे के बीच तीखी अनबन 28 दिसंबर, 2024 को पार्टी की आम सभा की बैठक के दौरान शुरू हुई थी. उस कार्यक्रम में रामदास ने अचानक अपनी बेटी के बेटे मुकुंदन को पीएमके युवा विंग का नेता नियुक्त करने की घोषणा कर दी. अंबुमणि ने मंच पर ही इस कदम का सीधा विरोध किया, जिससे तीखी बहस छिड़ गई. इसके बाद के महीनों में, पार्टी दो गुटों में बंट गई. रामदास ने अंबुमणि के वफादारों को पार्टी से निकालना और अहम प्रशासनिक पदों पर अपने समर्थकों को नियुक्त करना शुरू कर दिया.

उद्धव-देवेंद्र एक ही प्लेन में गए नागपुर

संयोग या कुछ और? महाराष्ट्र में हलचल तेज

मुंबई. महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक घमासान के बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुंबई से नागपुर जाने वाली एक ही फ्लाइट में साथ-साथ सफर करते नजर आए. यह अप्रत्याशित मुलाकात राज्य में चल रहे गंभीर राजनीतिक तनाव के समय हुई है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गहरी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद दोनों नेताओं ने कड़वाहट को दरकिनार रखते हुए सौहार्दपूर्ण अभिवादन किया और संक्षिप्त बातचीत की. इस फ्लाइट में शिवसेना (यूबीटी) के कई शीर्ष नेता भी सवार थे, जिनमें विधायक आदित्य ठाकरे, राज्यसभा सांसद संजय राउत और अनिल देसाई, और पूर्व सांसद विनायक राउत शामिल थे. शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि यह महज़ एक संयोग था. उन्होंने कहा कि यह कोई चार्टर्ड फ्लाइट नहीं थी, बल्कि एक रेगुलर सर्विस फ्लाइट थी.

मुख्यमंत्री शायद अपने चुनाव क्षेत्र नागपुर जा रहे होंगे. मुख्यमंत्री फड्डुणवीस और उद्धव ठाकरे का एक ही विमान में सफर करना, यूबीटी के छह सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच हुआ है. यह घटना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा हाल ही में यह घोषणा करने के बाद हुई है कि ऑपरेशन टाइगर अभी खत्म नहीं हुआ है.

> **संयोग या प्रयोग?**
>
> हालांकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हवाई जहाज में हुई यह मुलाकात महज एक संयोग थी, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की अत्यधिक अस्थिर दुनिया में, मुख्यमंत्री फडणवीस और ठाकरे के बीच किसी भी आमने-सामने की बातचीत आगामी विधानसभा चुनावों से पहले समीकरणों में बदलाव को लेकर गहन अटकलों को जन्म देगी.

पूरी रात रोई, सुवेंदु साथ खड़े रहे...

कोलकाता. बंगाल की राजनीति में इन दिनों बदलाव और पार्टी में खींचतान की चर्चाएं तेज हैं. इस बीच, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा का एक इंटरव्यू चर्चा का विषय बन गया.

इंटरव्यू में उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ अपने पुराने राजनीतिक और निजी संबंध को याद किया. महुआ ने कहा कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, जिन्हें समय और दल बदलने के बाद भी पूरी तरह भुलाया नहीं जा सकता. इंटरव्यू में महुआ ने एक पुराना पल भी साझा किया. उन्होंने बताया कि 2014 में उन्हें लोकसभा टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वह काफी निराश हुई थीं. उनके मुताबिक उस समय शुभेंदु अधिकारी ने उनका हौसला बढ़ाया था. महुआ ने यह भी कहा कि जब उन्होंने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा था, तो शुरुआती दौर में बहुत कम वरिष्ठ नेता उनके साथ दिखाई दिए, लेकिन शुभेंदु उनकी शुरुआती रैलियों में मौजूद रहे.

महुआ ने साफ किया कि अब दोनों अलग-अलग पार्टियों में हैं और पहले जैसी बातचीत नहीं होती.

विशेष | विधानसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से टीएमसी बाहर, बागी गुट का दबदबा

विधानसभा में ममता गुट को बड़ा झटका

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर जारी अंदरूनी खींचतान के बीच ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी समर्थक गुट को एक और बड़ा झटका लगा है. पश्चिम बंगाल विधानसभा की नवगठित बिजनेस एडवाइजरी (बीए) कमेटी में ममता गुट के किसी भी विधायक को शामिल नहीं किया गया है. विधानसभा की यह समिति सदन की कार्यवाही, विधेयकों की सूची और चर्चा के समय निर्धारण जैसे अहम फैसले लेती है.

जानकारी के अनुसार, समिति में विपक्ष के हिस्से में शामिल सभी स्थायी सदस्य ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले 'बागी' गुट से हैं. राजनीतिक जानकार इसे विधानसभा के भीतर बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत मान रहे हैं. हाल के दिनों में टीएमसी के भीतर बढ़ी गुटबाजी और विधानसभा में बागी विधायकों की बढ़ती भूमिका ने राज्य की राजनीति को नई दिशा दे दी है.

सदन की कार्यवाही तय करती है बीए कमेटी- दरअसल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक समितियों में से एक मानी जाती है. यह समिति प्रत्येक सत्र से पहले बैठक कर सदन की कार्यवाही का खाका तय करती है. सत्र की अवधि, कार्यसूची, पेश किए जाने वाले विधेयकों और विभिन्न विषयों पर चर्चा के समय निर्धारण जैसे अहम फैसले इसी समिति में लिए जाते हैं. सरल शब्दों में कहें तो विधानसभा की पूरी कार्यवाही के संचालन में इस समिति की केंद्रीय भूमिका होती है.

ऋतब्रत बनर्जी गुट का समिति में दबदबा- जानकारी के मुताबिक नवगठित बीए कमेटी की सूची के अनुसार, समिति में कुल 19 स्थायी सदस्य हैं. जबकी 14 सदस्य सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से और पांच सदस्य विपक्षी तृणमूल कांग्रेस से हैं.

हालांकि, विपक्ष के हिस्से में आए सभी पांच स्थायी सदस्य तृणमूल कांग्रेस के उस 'बागी लेकिन बहुमत' वाले गुट से हैं, जिसका नेतृत्व निष्कासित विधायक ऋतब्रत बनर्जी कर रहे हैं. वर्तमान में वही विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं. ऋतब्रत बनर्जी स्वयं भी बीए कमेटी के स्थायी सदस्य बनाए गए हैं.

> **10 नए सदस्यों को आमंत्रित किया गया**
>
> आपको बता दें कि स्थायी सदस्यों के अलावा समिति में 10 आमंत्रित सदस्य भी शामिल किए गए हैं. इनमें चार सदस्य भाजपा से और दो सदस्य तृणमूल कांग्रेस से हैं, जिनमें से एक ऋतब्रत बनर्जी गुट का प्रतिनिधि है. वहीं, विधानसभा में कांग्रेस के दो विधायकों में से एक मोहताब शेख को भी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है. इसके अलावा, माकपा के एकमात्र विधायक, नौशाद सिद्दीकी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया सेक्युलर फ्रंट के एकमात्र प्रतिनिधि तथा आम जनता उन्नयन पार्टी के अकेले विधायक को भी समिति में आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.